PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 308 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | शनिवार, 23 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जुलाई में बज जाएगा पंचायत-निकाय का चुनावी बिगुल

सरकार ने कोर्ट से दिसंबर तक का मांगा था समय, सरकार के साथ चुनाव आयोग को निर्देश

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को इसके निर्देश दिए हैं। वहीं ओबीसी कमीशन से कहा है कि वह 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। सरकार ने कोर्ट से दिसंबर तक का समय मांगा था। इससे पहले, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सरकार ने तय समय में नहीं कराए थे चुनाव :

दरअसल, हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए और हाईकोर्ट में चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगा दिया। सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं कराया जाना बताया था। इधर, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले डेढ़ साल से चुनाव टाल रही है।

'वन स्टेट-वन इलेक्शन' का दिया था तर्क :

सरकार की ओर से कहा गया था कि सितंबर से दिसंबर के बीच में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा। इससे 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की धारणा को भी बल मिलेगा। प्रार्थना पत्र में सरकार ने कहा था- कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हरसंभव प्रयास किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराया जाना संभव नहीं था। सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल, स्टाफ, ईवीएम सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर हाईकोर्ट से चुनाव आगे खिसकाने का अनुरोध किया था।

राज्य चुनाव आयोग ने समर्थन किया :

राज्य चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके चुनाव टालने का अनुरोध किया था। अपनी एप्लिकेशन में आयोग ने चुनाव की तिथियां बढ़ाने के सरकारी तर्कों का समर्थन करते हुए कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन के निर्धारण से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।

वंदे भारत में यात्रियों को राहत, साबरमती का अब जैसलमेर तक सीधा रेल सफर

जोधपुर में रेल मंत्री ने दी तीन नई ट्रेनों की सौगात, जैसलमेर में कोच केयर कॉम्प्लेक्स का किया शुभारम्भ

लोक टुडे। जोधपुर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां से उन्होंने जैसलमेर में बने नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच का कर दिया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। जोधपुर-लूणी-मारवाड़ जंक्शन रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की घोषणा भी हुई। इसके बाद रेल मंत्री विशेष ट्रेन से जालोर पहुंचे, जहां नई भुज-दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

जैसलमेर में कोच केयर कॉम्प्लेक्स शुरू, साबरमती ट्रेन का विस्तार

समारोह की शुरुआत में रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर बने नए कोच केयर परिसर को जनता को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस उद्घाटन से अब जैसलमेर में ही ट्रेनों के रखरखाव और साफ-सफाई की उच्च स्तरीय सुविधा मिल सकेगी।

वंदे भारत की क्षमता हुई तीन गुना

कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का नया स्वरूप रहा। इस ट्रेन को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच का कर दिया गया है। ट्रेन में 78 सीटों वाले 16 डिब्बे, 44 सीटों वाले 2 डिब्बे और 52 सीटों वाले 2 डिब्बे लगाए गए हैं। इससे ट्रेन की यात्री क्षमता 530 से बढ़कर सीधे 1440 हो गई है। 20 कोच वाली इस नई वंदे भारत के शुरू होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से बड़ी राहत मिलेगी।

भगत की कोठी में 400 करोड़ का नया कोचिंग टर्मिनल और डिपो का फेज-2 :

भगत की कोठी (बीजीकेटी) में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से एक नया 'मेगा कोचिंग टर्मिनल' विकसित करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही भगत की कोठी में ही तैयार हो रहे देश के पहले 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेंटेनेंस डिपो' के फेज-2 (मेंटेनेंस कम वर्कशॉप डिपो) की आधिकारिक घोषणा भी हुई। इसमें एक विश्वस्तरीय आवासीय ट्रेनिंग सेंटर बनेगा।

इसी के साथ पर्यटन नगरी जैसलमेर को गुजरात से सीधे जोड़ने के लिए साबरमती-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20486/20485) का जैसलमेर तक विस्तार किया गया है। रेल मंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

13 साल तक नहीं माना हाईकोर्ट का आदेश, अब कमिश्नर की कुर्सी कुर्क

लोक टुडे। जयपुर

जयपुर नगर निगम में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर ओम कसेरा की कुर्सी कुर्क करने के लिए टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंच गई। मामला 13 साल पुराने हाईकोर्ट आदेश की पालना नहीं किए जाने से जुड़ा है। एससीजेएम-1 जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने चंद्रकांत नागर बनाम जेडीए और अन्य मामले में यह कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद सेल अमीन बाबूलाल शर्मा, डिक्रीदार रश्मिकांत नागर और अधिवक्ता संजय शर्मा नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। यहां आयुक्त कार्यालय में कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से निगम अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई।

कोर्ट आदेश की अवहेलना :

दरअसल, यह मामला साल 2013 से जुड़ा हुआ है। परिवादी चंद्रकांत नागर की ओर से दायर मामले में 26 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने नगर निगम को आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद 13 साल बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन ने आवंटन पत्र जारी नहीं किया। लगातार आदेशों की अवहेलना और पालना नहीं होने के बाद मामला निचली अदालत पहुंचा। ACJM-1 जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए इसी महीने 20 मई को नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने माना कि लंबे समय तक आदेशों की अनुपालना नहीं होना न्यायालय की अवमानना के समान है।

कोर्ट की कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप :

कोर्ट की कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। नगर निगम के अधिकारियों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इतने सालों तक हाईकोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि यह मामला सरकारी विभागों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर सख्त संदेश माना जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय में पहुंचे कोर्ट अधिकारियों ने कमिश्नर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई की।

हालांकि बाद में मामले को लेकर कानूनी राय लेने और आगे की प्रक्रिया को लेकर निगम प्रशासन सक्रिय नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही यह मामला अब प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

हाईटेक होगा राजस्थान परिवहन: 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे पूरी तरह ऑटोमेटेड, 10 शहरों में आधुनिक बस पोर्ट की मंजूरी पर फोटो

उप मुख्यमंत्री बैरवा की अध्यक्षता में हुई परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा रोडवेज की संयुक्त समीक्षा बैठक में जारी किए निर्देश

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान सरकार ने राज्य में परिवहन सेवाओं को सुगम, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य के सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स को पूरी तरह से ऑटोमेटेड (स्वचालित) किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर अत्याधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और आमजन को विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है।

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा रोडवेज की संयुक्त समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को एक प्रभावी और मजबूत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। वही मौजूदा बस स्टैंडों की समय पर मरम्मत, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और नए बस स्टैंडों की स्थापना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का यह कदम न केवल राजस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई गति देगा। इस योजना पर जल्द ही धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

10 प्रमुख शहरों में वर्ल्ड-क्लास बस पोर्ट

प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे की तर्ज पर आधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इन बस पोर्ट्स में यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं जैसे- वातानुकूलित प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, वाई-फाई, डिजिटल डिस्प्ले, और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध होगी।

सरकार का यह कदम न केवल राजस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई गति देगा। इस योजना पर जल्द ही धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

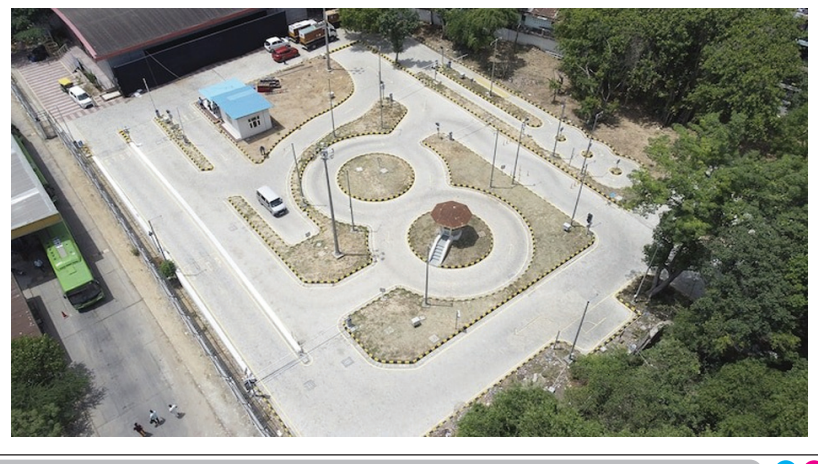

ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का पूर्ण स्वचालन

परिवहन विभाग के अनुसार, वर्तमान में संचालित सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स को अत्याधुनिक तकनीक और सेंसर से लैस किया जाएगा। इस बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाला टेस्ट पूरी तरह मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त होगा। इससे केवल योग्य चालकों को ही लाइसेंस मिल सकेगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

300 इलेक्ट्रिक और 300 नई रोडवेज बसें खरीदेंगे

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रोडवेज बेड़े के आधुनिकीकरण की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 300 इलेक्ट्रिक बसों एवं 300 नई रोडवेज बसों की खरीद प्रक्रिया मिशन मोड पर प्रगति पर है। सड़क सुरक्षा के तहत 3 हजार से अधिक चिकित्साकर्मियों को एडवांस लाइफ सपोर्ट तथा 15 हजार से अधिक नागरिकों को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से पुलिस विभाग को आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर, इंटरसेप्टर वाहन, रिफ्लेक्टिव क्रॉस बेल्ट एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) की स्थापना कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' योजना के तहत प्रथम चरण में 357 मार्गों पर बस संचालन किया जा रहा है, जिसमें कई मार्गों पर यात्री भार 100 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत नए कार्यादेश जारी किए गए हैं तथा शेष मार्गों पर निविदा प्रक्रिया जारी है।

सम्पादकीय

भीषण गर्मी और लू के बीच बढ़ता संकट

उत्तर और पश्चिमी भारत में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। हाल में कुछ राज्यों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब आसमान से फिर आग बरसने लगी है। दिन में लू चल रही है और रात में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। कृत्रिम उपकरणों के जरिए राहत पाने के लिए बिजली की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जून तक के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार पूर्वी-मध्य, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी। जाहिर है कि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ने से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। मगर सवाल है कि हर साल गर्मी, सर्दी और आंधी-बारिश के क्रम में इतना ज्यादा उतार-चढ़ाव क्यों आ रहा है? मौसम चक्र में इस बदलाव की वजह क्या है? क्या इसके पीछे प्राकृतिक कारण हैं या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मानव गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी छ्द्द्यद्धद्ध में बीते मंगलवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर-पश्चिमी हवाएं राजस्थान के थार रेगिस्तान और मध्य पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से दिल्ली की ओर बह रही हैं। विशाल शुष्क क्षेत्रों से गुजरते हुए ये हवाएं दिल्ली पहुंचते-पहुंचते बेहद शुष्क हो जाती हैं, जिससे गर्मी सतह के करीब बनी रहती है।

इस बीच दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7,776 मेगावाट से ज्यादा हो गई है, जो हाल के वर्षों की तुलना में मई में तेज वृद्धि को दर्शाती है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे, कूलर और एसी यानी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। मगर इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि एसी से निकलने वाली हानिकारक गैसों से जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वहीं इनकी वजह से स्थानीय तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। यानी जिन उपकरणों से घर को ठंडा रखने की कोशिश की जाती है, वही तापमान बढ़ने का कारण भी बनते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्मी, सर्दी, बारिश और बाढ़ की चरम स्थितियां जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि की वजह से पैदा हो रही हैं। इससे मौसम का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो रहा है। वनों की कटाई, शहरों में कंक्रीट के जंगलों का बढ़ता दायरा, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप तापमान सामान्य से अधिक हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मानव गतिविधियों को सीमित करने और चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए ठोस उपाय किए जाएं।

हाल में उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने और सटीक पूर्वानुमान को लेकर अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में इस दौरान चौबीस घंटों के भीतर सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। बहरहाल, अभी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में 24 मई तक लू की स्थिति बनी रहेगी।

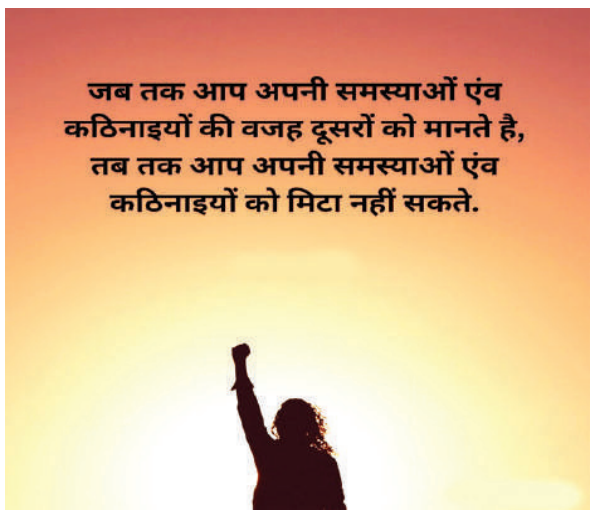

शुभेन्दु के सत्ता में आते ही बिलों में जा छिपे टीएमसी के गुंडे!

ट्रक चालकों से लिया जाने वाला भाइपो टैक्स खत्म

शुभेन्दु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस के गुंडाराज पर लगाम लगती दिखाई देने लगी है। इसका सबसे बड़ा फायदा झारखंड समेत सीमावर्ती राज्यों और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले ट्रक चालकों को होता दिख रहा है। वर्षों से जिन मार्गों पर 'भाइपो टैक्स' और 'डंडा टैक्स' के नाम पर टीएमसी समर्थित गुंडों द्वारा अवैध वसूली की जाती थी, वहां अब माहौल तेजी से बदल रहा है। ट्रक चालकों का कहना है कि जो लोग पहले बांस की बैरिकेडिंग लगाकर जबरन उगाही करते थे, वह अब कार्रवाई के डर से अपने बिलों में छिप गए हैं। सीमा पार करते समय नकद वसूली, धमकी, घंटों रोककर उत्पीड़न और वाहन को क्षति पहुँचाने जैसी घटनाओं में अचानक कमी आई है, जिससे लंबे समय बाद ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा से गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए पिछले कई दशकों से सफर केवल लंबी दूरी तय करने का मामला नहीं था, बल्कि रास्ते भर अवैध वसूली, धमकियों और देरी का सामना करने की मजबूरी भी थी। सीमा पार करते ही कई ट्रक चालकों को गिरोहों द्वारा लगाए गए अवैध नाकों, बांस की बैरिकेडिंग और डंडों से लैस लोगों का सामना करना पड़ता था। इन स्थानों पर नकद वसूली आम बात थी और विरोध करने पर चालकों को घंटों रोके रखना, गालियां देना, गाड़ी के शीशे तोड़ देना या टायर पंचर कर देना जैसी घटनाएं भी सामने आती थीं। अब हालात में अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है।

पश्चिम बंगाल में नौ मई को भाजपा सरकार बनने के बाद प्रशासन ने टीएमसी के उगाही केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अवैध वसूली नाके तुरंत हटाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे दोबारा सक्रिय नहीं हो सकें। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग दो और उससे जुड़ी राज्य सड़कों पर पहले की तुलना में यातायात काफी सुचारु हो गया है।

झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच माल ढुलाई करने वाले ट्रक चालकों का कहना है कि पिछले दो सप्ताह में उत्पीड़न और अवैध वसूली की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। गौरतलब है कि प्रतिदिन लगभग पचास हजार ट्रक पश्चिम बंगाल से होकर गुजरते हैं। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश के पांच प्रमुख पारगमन मार्गों को जोड़ने वाला यह राज्य देश की परिवहन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में सड़क परिवहन में आने वाली बाधाओं का असर व्यापार, आपूर्ति और समयबद्ध वितरण पर सीधा पड़ता था।

पश्चिम बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन महासंघ के महासचिव सजल घोष ने बताया कि यहां दो तरह की अनौपचारिक वसूली आम थी, जिन्हें स्थानीय लोग 'भाइपो टैक्स' और 'डंडा टैक्स' के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा कि 'भाइपो टैक्स' यानि भतीजा लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि 'डंडा टैक्स' भी पूरी तरह खत्म किया जाए। उल्लेखनीय है कि 'भाइपो टैक्स' शब्द का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर संकेत करते हुए किया जाता रहा है।

वहीं, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, झारखंड के मिहिजाम सीमा क्षेत्र के पास रुपनारायणपुर इलाके में ट्रक चालकों और स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले सड़क किनारे कई स्थानों पर अवैध वसूली होती थी, लेकिन अब वहां यातायात बिना किसी रुकावट के चल रहा है। एक स्थानीय ई-रिक्शा चालक ने मीडिया से कहा कि चार मई के बाद से अधिकांश अवैध वसूली केंद्र बंद हो गए हैं। चालकों का कहना है कि पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया जिलों में अनेक जगहों पर पैसे देने के लिए रोका जाता था। यदि कोई चालक भुगतान से इंकार करता था तो उसे घंटों परेशान किया जाता था। एक ट्रक चालक ने मीडिया को बताया कि पहले हर कुछ किलोमीटर पर बांस की बैरिकेडिंग लगी रहती थी और सड़क पर खड़े लोग जबरन पैसे मांगते थे। यदि कोई चालक रसीद मांगता था तो माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता था। भुगतान से इंकार करने पर वाहन के शीशे तोड़ दिए जाते थे या टायर पंचर कर दिए जाते थे। कई चालकों ने आरोप लगाया कि इन गतिविधियों के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय थे, जो लंबे समय से हाईवे पर प्रभाव बनाए हुए थे।

सबसे अधिक परेशानी जल्दी खराब होने वाले सामान ढोने वाले वाहन चालकों को उठानी पड़ती थी। सब्जियां, मछली और अन्य नाशवान वस्तुओं को समय पर बाजार तक पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। अखिल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद आकिल सोनू ने कहा कि हर घंटे की देरी से नुकसान बढ़ता था, लेकिन वसूली करने वाले गिरोहों को इससे कोई मतलब नहीं था कि माल खराब हो रहा है या व्यापारियों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

ट्रक चालकों का कहना है कि मौजूदा कार्रवाई से उन्हें काफी राहत मिली है। अब कई मार्गों पर बिना अनावश्यक रुकावट के आवाजाही हो रही है और माल समय पर पहुंचने लगा है। हालांकि चालक और परिवहन संगठन यह भी मानते हैं कि केवल अस्थायी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। यदि प्रशासन लगातार निगरानी नहीं रखता तो भविष्य में ऐसे अवैध नाके दोबारा सक्रिय हो सकते हैं।

बहरहाल, राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और गुंडाराज पर सख्ती से अंकुश लगाने की दिशा में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी द्वारा उठाए गए कदमों की आम लोगों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े संगठनों के बीच व्यापक सराहना हो रही है। ट्रक चालकों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें सड़कों पर भयमुक्त माहौल महसूस हो रहा है। लोगों का मानना है कि यदि इसी तरह प्रशासनिक सख्ती जारी रही तो पश्चिम बंगाल में व्यापार, परिवहन और निवेश का माहौल और बेहतर होगा तथा आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा।

आवारा कुत्तों की भयावह समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकिन जिम्मेदारी तय किए बिना कैसे बनेगी बात?

देश की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और दूसरी जगह भेजने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत देश भर में कुत्ता काटने की घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में अपने पहले के आदेश की फिर से याद दिलाते हुए कहा कि सड़क के कुत्तों पर 7 नवंबर, 2025 को दिया गया उनका आदेश ही लागू होगा। इन आदेशों को लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और जो अधिकारी इनका पालन न करे, उन पर विभागीय और अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।

लेकिन क्या इससे देश के आम नागरिकों को खुश होना चाहिए? क्या इससे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों – खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल पाएगी? यह इतना भी आसान नहीं है। जब तक किसी खास अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद व्यवहारिक स्थिति तो यही है कि ज्यादातर राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लेती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए इस आदेश को लागू करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी यानी सीधे छ्रू को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए गए आदेश के 6 महीने बीत जाने के बावजूद हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का नगर निगम – स्ष्टष्ठ कुत्तों को रखने के लिए एक डॉग सेंटर तक तैयार नहीं कर पाई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो कुत्ता एक से अधिक बार लोगों को काट चुका हो, उसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद समेत राज्य के कई जिलों में भी अभी भी जरूरी डॉग सेंटर का निर्माण फाइल्स में ही अटका पड़ा है। क्या इस तरह की लापरवाही और लेट-लतीफी के लिए जिलों के सीएम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? समय आ गया है कि हर जिले, हर राज्य और सबसे ऊपर सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए जिस पर कॉल करने वाले हर व्यक्ति को तुरंत उनकी शिकायत का एक नंबर भी अलॉट कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो टोल फ्री नंबर पर बैठने वाले अदालत के स्टॉफ का खर्चा भी लोगों से ले सकता है और इसके लिए प्रति कॉल 3 से 5 रुपए की राशि भी फिक्स की जा सकती है लेकिन हर कॉल का उचित फॉलोअप सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।

इस काम को युद्धस्तर पर करने की जरूरत है क्योंकि भारत में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। वैसे तो देश में कुत्तों द्वारा काटने के सारे आंकड़े दर्ज नहीं करवाए जाते हैं लेकिन जो भी आंकड़े दर्ज होते हैं, उसके मुताबिक वर्ष 2024 में हर मिनट पर डॉग बाइट के 7, हर घंटे में 430, रोजाना 10,321 , हर महीने 3,09,643 और वर्ष भर में 37,15,713 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी सरकार भी यह मान रही है कि एक साल में 37 लाख से भी ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं। वहीं वर्ष 2025 में कुत्तों के काटने की संख्या 47 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है।

सरकारी रिपोर्ट की माने तो, भारत में हर साल रेबीज के कारण 300 लोगों की मौत होती है। लेकिन ङ्ख॥ह्र के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 18 से 20 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। यहां इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस तरह के ज्यादातर मामले आंकड़ों में दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2019 में हुई पशु जनगणना में, देश में आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ बताई गई थी। लेकिन एक मोटे अनुमान के तौर पर यह माना जाता है कि देश में वर्तमान में आवारा कुत्तों की संख्या 6 से 7 करोड़ के लगभग हो गई है। यह समस्या हर गुजरते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। मोहल्लों, कॉलोनियों, सोसायटियों यहां तक कि पार्कों में भी इन आवारा कुत्तों ने कब्जा जमा रखा है। लगभग हर मोहल्ले/कॉलोनी और सोसायटी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन्हें अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिलाएंगे, बल्कि उनकी जिद होगी कि वो इन्हें बाहर ही खाना खिलाएंगे।

आसान होती अच्छी शिक्षा तक पहुंच

एक समय था जब भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की डगर बहुत कठिन हुआ करती थी। फीस, रहने का खर्च और वीजा की लागत तो ज्यादा थी ही, साथ ही उन्हें भाषा की दिक्कतों और परिवार से दूर रहने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। विदेश जाकर पढ़ाई करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हालांकि यह अब भी आसान नहीं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए नए अवसर आ गए हैं। दुनिया की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं अब भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने कैंपस यहां खोल रही हैं। भारत ने भी उन्हें यहां लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। किसी संस्थान को यहां आने के लिए दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में होना चाहिए या उस संस्थान की किसी खास विषय में असाधारण विशेषज्ञता होनी चाहिए। कई संस्थाओं ने भारत में अपने कैंपस खोल दिए हैं या खोलने की घोषणा कर दी है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी आफ एबरडीन की पांच सौ साल की शैक्षणिक विरासत है। यूनिवर्सिटी आफ साउथैंपटन के दुनिया भर में 2.85 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं।

यूनिवर्सिटी आफ वोलोंगोंग का मानना है कि अच्छी विश्वस्तरीय शिक्षा और वैश्विक करियर हर छात्र की पहुंच में होने चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। ये विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान अपने साथ गहरा अनुभव और शैक्षणिक व्यवस्था ला रहे हैं। वे भारत में ऐसे आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं, जो भारत के युवाओं के लिए उत्साहपूर्ण और उपयोगी हैं, जैसे टेक्नोलाजी, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और फाइनेंस। एक समय था जब इन संस्थानों में पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए यह न तो किफायती था, न सुलभ। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भारतीय कैंपस में पढ़ने वाला छात्र वही डिग्री पाता है, जो उसे विश्वविद्यालय के मूल कैंपस में पढ़ने पर मिलती। इससे छात्रों के लिए न सिर्फ खर्च कम हुआ है, बल्कि कई संस्थान तो अपने शुरुआती वर्षों में छात्रवृत्तियां भी दे रहे हैं। कुछ को मिलने वाले अवसर अब सबके लिए उपलब्ध हैं। भारत एक युवा देश है और अच्छी उच्च शिक्षा देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। यहां लाखों ऐसे सक्षम और मेहनती छात्र हैं, जिन्हें सीटों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उत्कृष्ट संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। भारत में अपनी क्षमता बढ़ा रहे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भारत की इस वास्तविक और तात्कालिक आवश्यकता को भी पूरा कर रहे हैं। उनका आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि भारतीय छात्रों को नए विकल्प देता है। इस दृष्टि से इनका आना शिक्षा क्षेत्र में एक आवश्यक कदम है। क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ विविधता भी महत्वपूर्ण है।

जहां एक तरफ भारतीय उच्च शिक्षा कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, वहीं दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें विकास की आवश्यकता है। विदेशी संस्थान अपने साथ विभिन्न बौद्धिक माहौल में विकसित अध्ययन शैली, शोध की परंपरा और नए पाठ्यक्रम संरचनाएं लाते हैं।

विशेष आलेख /राशिफल

कानून एवं व्यवस्था की मिसाल

आज अपराधी और माफिया तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रवैये की चर्चा सारे देश में होती है, लेकिन प्रदेश की राजनीति का एक लंबा दौर ऐसा भी रहा है, जब अपराध केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं था, बल्कि सत्ता, जातीय समीकरण और राजनीतिक अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर राजनीतिक दलों में तनाव पैदा होता था, अधिकारियों के तबादले होते थे और गठबंधन टूटने की नौबत तक आ जाती थी। वर्ष 1994 में कुख्यात गैंगस्टर महेंद्र फौजी का एनकाउंटर उस दौर का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह केवल एक दुर्दांत अपराधी के मारे जाने की घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट था, जिसने तत्कालीन सत्ताधारी गठबंधन (सपा और बसपा) में ऐसी दरार डाल दी, जो आगे चलकर 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड तक पहुंची और फिर वह कभी भर नहीं सकी।

आज के दौर में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति की चर्चा होती है, तब पिछली सदी के अंतिम दशक का वह दौर और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यह फर्क केवल सरकारों का नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण का भी है। तब और अब का अंतर समझने के लिए जेन जी को महेंद्र फौजी के बारे में जानना आवश्यक है। पिछली सदी के अंतिम दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र फौजी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक फैले नेटवर्क वाला कुख्यात गैंगस्टर था। अप्रैल, 1994 में बुलंदशहर पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन जल्द ही इस सफलता का स्वाद फीका पड़ गया। पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए सत्ताधारी पार्टियां आपस में भिड़ गईं। एक अपराधी के एनकाउंटर के लिए एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया-वह भी एक बार नहीं दो बार!

बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी ओपी सिंह (बाद में डीजीपी बने) को हटाकर लखनऊ भेजा गया और फिर कुंभ मेले का एसएसपी बनाया गया। पुलिस पर इतने भारी दबाव के पीछे जातीय समीकरण काम कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर तो जातीय समीकरण साधने का दबाव हमेशा होता है। यह राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी थी कि एक कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर के बाद पुलिस का मनोबल न टूटने दिया जाए। स्वयं ओपी सिंह ने स्वीकार किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने उनसे साफ कहा था कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो सरकार गिर सकती है। यह बयान उस दौर की राजनीति को समझने के लिए पर्याप्त है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध और सत्ता के गठजोड़ की चर्चा महेंद्र फौजी तक सीमित नहीं रही। आगे चलकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कई नाम इस राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। सदन से लेकर सड़क तक अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नाम कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे। इससे यह धारणा मजबूत होती गई कि अपराध और राजनीति के बीच का गठजोड़ अटूट हो गया है। वर्ष 2017 के बाद जब योगी सरकार ने माफिया पर सीधी कार्रवाई शुरू की, तो उसे केवल प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि दबावों से मुक्त एक नए राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा गया। माफिया को मिट्टी में मिला देने का योगी माडल प्रदेश भर में अपराध के खिलाफ जीरो टालरेंस माडल के रूप में लागू हुआ। कौन भूल सकता है 2023 में प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल के करीबी उमेश पाल की सरेआम हत्या को, जिसे अतीक अहमद के लड़के समेत कई अपराधियों ने अंजाम दिया था। इस घटना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यह बयान आगे चलकर उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रतीक बना। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में 10 हजार से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हुईं। इनमें सैकड़ों अपराधी मारे गए, हजारों घायल और गिरफ्तार हुए। 75 से अधिक माफिया की 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की गई। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी व्यापक कार्रवाई हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे अपराधियों पर हुई कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि अब कानून का शिकंजा जाति, धर्म या राजनीतिक संरक्षण देखकर नहीं चलेगा। योगी सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और तुष्टीकरण आधारित कार्रवाई की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से अलग एक नए प्रशासनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। सरकार बदलने के साथ धारणा भी बदली। महेंद्र फौजी का मामला उस दौर का प्रतीक था, जब अपराध, जातीय समीकरण और सत्ता की राजनीति एक-दूसरे में उलझी हुई थीं। अपराधियों का मनोबल तोड़ने के बजाय ये समीकरण पुलिस का मनोबल तोड़ते थे।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष — परिवार और कार्य के क्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार से संघर्ष टाल सकेंगे। वाणी पर नियंत्रण नहीं होने से किसी के साथ वाद-विवाद या झगड़ा होने की आशंका रहेगी।

सिंह — आर्थिक आयोजनों और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए उत्तम दिन है। व्यापार-धंधे में लाभ, नौकरी में पदोन्नति और आय के स्रोत में वृद्धि होने से आप आनंद और संतोष की भावना का अनुभव करेंगे।

धनु — नकारात्मक विचारों से मन में हताशा जन्म लेगी। इस समय मानसिक उद्वेग और क्रोध की भावना अनुभव होगी। खर्च बढ़ेगा। वाणी पर संयम न रहने के कारण परिवार में मनमुटाव और झगड़े होने की संभावना है।

वृषभ — आपका आज का दिन मिश्र फलदायी साबित होगा। बौद्धिक कार्यों और व्यवसाय में नई विचारधारा अमल में लाएंगे। लेखन और साहित्य से संबंधित प्रवृत्तियों में आपकी सृजनात्मकता दिखाई देगी।

कन्या — आर्थिक और व्यापारिक आयोजन करने के लिए आज का दिन शुभ है। कार्य सरलतापूर्वक सफल होंगे। परोपकार की भावना आज बलवती रहेगी।

मकर — दैनिक घटना चक्र की प्रवृत्तियों में आज परिवर्तन आएगा। आज आप मौज-मस्ती और मनोरंजन की दुनिया में घूमने के मूड में होंगे। इसमें मित्रों, परिजनों का साथ मिलेगा।

मिथुन — आकस्मिक धन लाभ का दिन है। आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उत्तम दिन है। फिर भी नए काम शुरू न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।

तुला — आपका आज का दिन धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यतीत होगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के संयोग बनेंगे। विदेश गमन के लिए अवसर निर्मित होंगे।

कुंभ — तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभदायक और सफल दिन है। आपके कार्यक्षेत्र में आप वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक पूरा होगा।

कर्क — आपकी वाणी या व्यवहार से आज किसी के साथ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। परिजनों तथा सगे- संबंधियों के साथ खूब संभलकर रहना पड़ेगा। बीमारी या दुर्घटना का योग है, सावधानी बरतें।

वृश्चिक — विचारों की दृढ़ता के साथ आप सावधानीपूर्वक काम करेंगे। व्यवस्थित रूप से आर्थिक विषयों का आयोजन कर सकेंगे। वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा।

मीन — आज का दिन मीन राशि वाली महिलाओं का सुख-शांति से व्यतीत होगा। व्यापारियों को भागीदारी के लिए उत्तम समय है। दांपत्य जीवन में निकटता का अनुभव होगा।

ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम | केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाएं बन रही सशक्त

लखपति दीदी योजना में ब्याज घटाकर ऋण सीमा बढ़ाई, प्रदेश में पारदर्शिता से भर्ती परीक्षाएं हुई आयोजित-सीएम

मुख्यमंत्री ने दो सीएलएफ को अनुदान आधारित ट्रैक्टर्स की चाबियां सौंपी

लखपति दीदियों से किया संवाद, डाटा सखी एवं पोषण सखी को दिया टेबलेट

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला के सर्वांगीण विकास के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घर-घर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेण्डर एवं हर घर नल से जल योजनाओं के जरिए महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है।

मुख्यमंत्री डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्रों को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ पहुंचा रही है। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूटी एवं साइकिलों का वितरण किया गया है। गर्भवती महिलाओं को मा वाउचर योजना के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाएं सशक्त बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में राजीविका के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, 17 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने से वे आर्थिक रूप से सशक्त भी बनी हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका बहनों के लिए हमारी सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये एवं ब्याज दर 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत वार्षिक किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करने के क्रम में सवा लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। सवा लाख पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी किया है, वहीं 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाएं भी प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से पूरी हुई हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया कोटा शहर का निरीक्षण

यातायात, सड़क और नागरिक सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कोटा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, सड़कों, अतिक्रमण और आमजन से जुड़ी सुविधाओं की मौके पर समीक्षा की तथा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम कर समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान श्री बिरला ने कहा कि कोटा शहर का विकास व्यवस्थित और दूरदृष्टि के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर आवागमन और सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने यातायात व्यवस्था सुधारने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने पर जोर दिया।

लोकसभा अध्यक्ष ने केडीए को सभी राजकीय विभागों पर एक जैसे ग्लो साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि शहर में एकरूपता दिखाई दे। उन्होंने प्रमुख चौराहों पर स्लिप लेन चौड़ी करने, अतिक्रमण हटाने और सड़क पर पार्किंग की स्पष्ट मार्किंग करवाने को कहा। साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि निर्धारित स्थानों के बाहर सड़क पर वाहन खड़े न हों, इसकी प्रभावी निगरानी की जाए।

न्यूज इन बॉक्स

जयपुर में 10 हजार महिलाएं एक साथ करेंगी घूमर डांस

आपणो घूमर कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का होगा प्रयास; पोस्टर किया लॉन्च

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर में 10 हजार महिलाएं एक साथ घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी और विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और नारी शक्ति के प्रतीक लोकनृत्य घूमर को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जाएगा। सद्भावना परिवार की ओर से 1 अगस्त को आपणो घूमर-2026 का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का पोस्टर गुरुवार को जवाहर सर्किल पर लॉन्च किया गया।

संस्था अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया- यह आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राजस्थान की समृद्ध परंपरा, महिला सशक्तीकरण और सामूहिक सांस्कृतिक चेतना का भी प्रदर्शन बनेगा। आयोजकों के अनुसार- कार्यक्रम में राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं हिस्सा लेंगी।

खेल से फिटनेस, तकनीक से भविष्य - केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने युवाओं को दिया नया विजन

गिर कर भी फिर उठ खड़ा होना सिखाते हैं खेल - केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

जयपुर(नि.सं.)। एशियन बीच गेम्स कबड्डी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी श्री जय भगवान का खैरथल-तिजारा जिले के जाट भगोला मुंडावर में आयोजित सम्मान समारोह में स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने संख्या में खेल प्रेमी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने साफा पहनाकर श्री जय भगवान का सम्मानित किया तथा उनकी उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है।

वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय को राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक सम्पन्न

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों हेतु 232 करोड़ रुपये की कार्ययोजना का अनुमोदन

जयपुर(नि.सं.)। मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम वाईब्रेंट विलेज की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति का आयोजन शासन सचिवालय में किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट रहने वाले समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, विश्वास स्थापित करने तथा सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए सीमा क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें, जागरूकता अभियान आयोजित करने के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए।

मुख्य सचिव द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से टेलीकॉम एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव प्रेषित करने पर जिला कलक्टरों की प्रशंसा की गई। दूरदर्शन और बीएसएनएल के अधिकारियों से उक्त क्षेत्र में 4जी टेलीकॉम कनेक्टिविटी एवं टेलीविजन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि वाईब्रेंट विलेज योजना सीमान्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों का समग्र विकास करने सम्बन्धित केन्द्र की दूसरी बड़ी योजना है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2025-26 के अनुसरण में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांवों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रूपयें प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है।

चम्बल अभयारण्य में बजरी माफिया पर

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद कार्रवाई में आई और तेजी

जयपुर (नि.सं.)। राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत/बजरी के खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिए महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2025 के प्रारम्भ से ही लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी निरंतर कार्रवाई के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ मोटो सिविल रिट में गत 17 अप्रैल 2026 को जारी किए गए निर्देशों की पालना में अब इस अभियान को और अधिक व्यापक व गति प्रदान की गई है। पुलिस मुख्यालय की अपराध शाखा के विशेष पर्यवेक्षण में जिला धौलपुर और जिला करौली पुलिस द्वारा संयुक्त व प्रभावी समन्वय स्थापित कर चम्बल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को लगातार जारी रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) वी.के.सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा पूर्व से ही संचालित इन कार्यवाहियों के तहत वर्ष 2025 के प्रारम्भ से लेकर माह अप्रैल 2026 तक की अवधि में दोनों जिलों में रिकॉर्ड 392 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस अनुसंधान की त्वरित गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्ज किए गए इन कुल मुकदमों में से 342 प्रकरणों में पुलिस द्वारा गहन तफ्तीश पूर्ण कर माननीय न्यायालयों के समक्ष आरोप पत्र भी पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल: अब 14 हजार छात्रों की परीक्षा अधर में, केवल आवेदन में संशोधन का मौका मिला

जयपुर (नि.सं.)। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-1 की परीक्षा में 14122 विद्यार्थी आवेदन में त्रुटि के कारण परीक्षा से वंचित हो गए थे। इन विद्यार्थियों की परीक्षा पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे वे असमंजस में है। स्टेट ओपन ने अभी तक इनकी परीक्षा के आयोजन का निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इन विद्यार्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका मिल गया है। वे अपने आवेदन में त्रुटि में सुधार कर सकेंगे। इसके लिए 22 से 26 मई तक पोर्टल को खोला जाएगा।

साथ ही निर्धारित अवधि के बाद मौका नहीं मिलेगा। स्टेट ओपन की अप्रैल-मई में आयोजित स्ट्रीम-1 की परीक्षा के लिए पिछले साल आवेदन लिए थे। 92 हजार आवेदन आए थे, इनमें से 14122 में त्रुटि थी।

जनता कॉलोनी एवं खरेखड़ी को मिले सामुदायिक भवन

अजमेर स्वच्छ, श्रेष्ठ एवं आधुनिक शहर के रूप में उभरेगा- विधानसभा अध्यक्ष, वासुदेव देवनानी

जयपुर। अजमेर शहर के वार्ड 77 स्थित जनता कॉलोनी में नगर निगम द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम खरेखड़ी में विधायक कोष से निर्मित 16.65 लाख रुपए लागत के सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। जनता कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि नगर निगम द्वारा निर्मित यह सामुदायिक भवन क्षेत्रवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से उनका आत्मीय जुड़ाव रहा है तथा बीते दो वर्षों में वार्ड एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 6.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बालाजी नगर से झूलेलाल कॉलोनी तथा भास्कर कार्यालय से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण सहित अनेक सड़कों का निर्माण कराया गया है। वैशाली नगर क्षेत्र में लगभग सभी सड़कें पक्की की जा चुकी हैं तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नव अजमेर के निर्माण की दिशा में अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। अजमेर प्रवेश मार्ग पर 8 करोड़ रुपए से अधिक लागत से सौंदर्यकरण कार्य किए जा रहे हैं। इससे शहर में प्रवेश करते ही आगंतुकों को सुखद अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा प्लॉट्स के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इससे

स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 34 करोड़ रुपए लागत के कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। इसके निर्माण से बड़े स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन के लिए आधुनिक स्टेडियम विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

चपरासी भर्ती में जीरो नंबर वालों को नहीं मिलेगी नौकरी

जयपुर (नि.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाते जीरो कट ऑफ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा- भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी है। बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर-संवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करने की छूट दी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मिला एफएओ का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मैडल देश के अन्नदाताओं का सम्मान

हमारी कृषि नीतियों को वैश्विक मान्यता की पहचान- संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल

जयपुर(नि.सं.)। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूएन की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंगयु द्वारा इस संस्था के रोम (इटली) स्थित मुख्यालय के ऐतिहासिक प्लेनरी हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान एग्रिकोला मेडल से सम्मानित करना देश के करोड़ों अन्नदाताओं का सम्मान है। यह

भारत की सुदृढ़ होती कृषि नीतियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता और सम्मान है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हमारे अटूट संकल्प को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री के उन असाधारण प्रयासों को मान्यता देता है, जिन्होंने देश से भुखमरी समाप्त करने, गरीबी कम करने तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा व पोषण सुनिश्चित करने में मील का पत्थर स्थापित किया है।

कोर्ट के आदेश | जयपुर नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के आदेश

निगम मुख्यालय पहुंची टीम, 13 साल तक हाईकोर्ट के आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर नगर निगम में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर ओम कसेरा की कुर्सी कुर्क करने के लिए टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंच गई। मामला 13 साल पुराने हाईकोर्ट आदेश की पालना नहीं किए जाने से जुड़ा है। एससीजेएम-1 जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने चंद्रकांत नागर बनाम जेडीए और अन्य मामले में यह कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद सेल अमीन

बाबूलाल शर्मा, डिक्रीदार रश्मिकांत नागर और अधिवक्ता संजय शर्मा नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। यहां आयुक्त कार्यालय में कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से निगम अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई।

कोर्ट आदेश के बाद भी जारी नहीं किया आवंटन पत्र

दरअसल, यह मामला साल 2013 से जुड़ा हुआ है। परिवादी चंद्रकांत नागर की ओर से दायर मामले में 26 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने नगर निगम को आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद 13 साल बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन ने आवंटन पत्र जारी नहीं किया।

लगातार आदेशों की अवहेलना और पालना नहीं होने के बाद मामला निचली अदालत पहुंचा। ACJM-1 जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए इसी महीने 20 मई को नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने माना कि लंबे समय तक आदेशों की अनुपालना नहीं होना न्यायालय की अवमानना के समान है।

जयपुर में IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा

3 सटोरिए गिरफ्तार: लोगों को 'DX-13' सट्टा लाइन से जोड़ते थे

मकान से लेपटॉप, हिसाब-किताब की डायरी जब्त

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने IPL क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार का देर रात भंडाफोड़ किया है। एक मकान की घेराबंदी कर तीन सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से लाखों रुपए का सट्टा हिसाब-किताब सहित बड़ी संख्या में उपकरण जब्त किए है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सटोरिए DX-13 सट्टा लाइन से लोगों को जोड़कर सट्टा लगवा रहे थे।

खोरा बिसल इलाके में स्थित मकान से सटोरियों को पकड़ा- स्पेशल ऑपरेशन्स कमिश्नर ओमप्रकाश की मॉनिटरिंग में खोरा बिसल इलाके में कार्रवाई की गई। सीएसटी को सूचना मिली कि खोरा बिसल इलाके में गोविन्द नगर स्थित एक मकान में ढ्कक्र क्रिकेट मैच को लेकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस टीम ने सूचना पर मकान की घेराबंदी कर दबिश दी। मकान के अंदर दबिश देने पर तीन आरोपी प्रदीप कुमार, अंकित व संजय क्रिकेट मैच पर सट्टा कारोबार करते मिले।

हिसाब-किताब की डायरी, लेपटॉप समेत अन्य सामान जब्त- सटोरिए DX-13 सट्टा लाइन से लोगों को जोड़कर क्रिकेट मैच सट्टा लगवाते मिले। तीनों आरोपियों के कब्जे से 18 मोबाइल, 5 लेपटॉप, 24 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 5 सट्टा डायरी (लाखों रुपए का हिसाब-किताब) और एक वाई-फाई राउटर जब्त किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर अवैध सट्टा कारोबार के नेटवर्क की जानकारी की जा रही है।

फील्ड विजिट से योजनाओं का जरूरतमंदों तक पहुंचाएं लाभ

जल जीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता से करें पूर्ण- मुख्यमंत्री

डूंगरपुर में प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए बने कार्ययोजना

वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान में बढ़ाएं जन भागीदारी

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिला कलक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट कर आमजन की समस्याओं को सुनने तथा उनके त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को विभागीय योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाए।

उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि

सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करके योजनाओं को धरातल पर उतारें। उन्होंने जिला कलक्टर को सभी उपखण्ड एवं विभागीय अधिकारियों की फील्ड विजिट सहित विभागीय जिम्मेदारियों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों की जमीने बहुत छोटी हैं, इसलिए उन्हें कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिससे उनकी उपज और आय में वृद्धि हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में पशुपालकों को विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूक कर लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा में आम की गुणवत्ता बहुत अच्छी है तथा मक्का की पैदावार भी अच्छी होती है। इसलिए यहां प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए। जिससे किसानों को अच्छी आमदनी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।

मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने, जल स्रोतों की साफ सफाई करने एवं कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय के कार्यों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बारिश के पानी का संचय कर उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाएं। इसके लिए जल संसाधन और पीएचईडी विभाग मिलकर काम करें।

गोडावण दिवस पर आयोजित हुआ गरिमामय समारोह

राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध- वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री

जयपुर (नि.सं.)। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन एवं जैव विविधता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जैसलमेर स्थित उत्कर्ष जैन भवन में गोडावण दिवस उत्साह, जागरूकता एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रदेश सरकार द्वारा गोडावण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

वन राज्य मंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के राज्य पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रभावी एवं दूरगामी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गोडावण केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक धरोहर एवं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके संरक्षण के लिए सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक एवं जनसहभागिता के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा संचालित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर सम व रामदेवरा संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। गोडावण की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा उनकी प्रजनन क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुर्लभ पक्षी को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

न्यूज ब्रीफ

3500 पदों पर निकाली भर्ती; 2 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी

जयपुर (नि.सं.)। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को, खासकर नर्सिंग और केयरगिविंग सेक्टर से जुड़े उम्मीदवारों के लिए खुशखबर है। इजराइल में होम-बेस्ड केयरगिवर के 3500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने करीब 2 लाख रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

यह भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। इस भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कुल पदों में करीब 90 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए और 10 प्रतिशत सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं।

नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, केयरगिविंग या संबंधित क्षेत्र का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

एवरेस्ट से उतरते वक्त दो भारतीयों की मौत: ज्यादा थकान से सांसें फूल गई थीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दो भारतीय पर्वतारोहियों की उतरते समय मौत हो गई। यह जानकारी शुक्रवार को नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि भंडारी ने दी। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे नामक पर्वतारोही एवरेस्ट से उतरते समय बुरी तरह थक गए थे। इससे उनकी सांसें फूल गई थीं। एवरेस्ट फतह कर लौट रहे थे भंडारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि ऋषि भंडारी के मुताबिक संदीप आरे ने बुधवार को, जबकि अरुण तिवारी ने गुरुवार को शाम करीब 5.30 बजे एवरेस्ट को फतह किया था। अरुण तिवारी की मौत हिलेरी स्टेप के पास हुई। वहीं, संदीप अरे को शेरपा रेस्क्यू टीम कैंप-2 तक ले आई थी। कैंप पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। बुधवार को तीन भारतीयों ने एवरेस्ट फतह किया बुधवार को संदीप रे समेत तीन भारतीय पर्वतारोहियों ने 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचे थे।

ऑपरेशन सिन्दूर पर प्रत्येक भारतीय को गर्व, अब भारत मुंहतोड़ जवाब देता है- देवनानी

जयपुर(नि.सं.)। ऑपरेशन सिन्दूर की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया है कि अब हम हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। युवा कैडेट्स अपने जीवन में मर्यादा, अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता को आत्मसात करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारत ने पूरे विश्व को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत है जो किसी से नहीं डरता। विधानसभा अध्यक्ष ने स्कूल के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी कैडेट से आह्वान किया कि वे अनुशासन को अपने जीवन में आत्मसात करें।

एक पेड़ मां के नाम : मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक

हमारा लक्ष्य: पौधे लगें और पौधे पेड़ बनें- पंचायती राज मंत्री

जयपुर(नि.सं.)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में एक पेड़ मां के नाम : मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों तथा गत वर्षों में किए गए पौधारोपण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए एक पेड़ मां के नाम 2.0 : मिशन हरियालो राजस्थान को जनभागीदारी के साथ व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 में 3.61 करोड़ पौधारोपण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिलावर ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि लगाए गए पौधे जीवित रहें और आगे चलकर पेड़ बनें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण के साथ-साथ पौधों की नियमित मॉनिटरिंग, सुरक्षा एवं देखरेख भी सुनिश्चित की जाए।उन्होंने शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों से पौधारोपण अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट बॉर्डर' सुरक्षा सिस्टम लागू होगा

हर अवैध घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे: अमित शाह

नई दिल्ली (नि.सं.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले एक साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी। इसके तहत ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा की निगरानी मजबूत की जाएगी, ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके।

दिल्ली में क्स्न के रुसतमजी मेमोरियल लेक्चर और क्स्न इन्वेस्टिचर सेरेमनी को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार की अवैध घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उसे वापस भेजा जाएगा।

घुसपैठ जनसंख्या बदलने की साजिश

अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। उन्होंने क्स्न जवानों से कहा कि वे इस कोशिश को सफल नहीं होने दें और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करें। गृह मंत्रालय जल्द ही एक हाई-पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मामलों की निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग देना होगा।

एसएमएस-अस्पताल में मरीज को अनफिट बताकर बिना ऑपरेशन किया डिस्चार्जपरिजनों ने रुपए मांगने का लगाया आरोप

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मरीज से रुपए मांगने और बिना ऑपरेशन डिस्चार्ज का परिजनों ने आरोप लगाया। छत से गिरे बुजुर्ग मरीज से पहले तो ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांग गए। वहीं पूरे रुपए नहीं मिले तो बिना ऑपरेशन किए मरीज को ये कहकर डिस्चार्ज कर दिया कि वह ऑपरेशन के लिए अभी फिट नहीं है। करीब एक महीने बाद फिट हो जाए, तब आना। वहीं मरीज के परिजन मजबूरन उसी दिन प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां अगले दिन सफल ऑपरेशन हो गया। डीग जिले के कुम्हेर के रहने वाले भरतसिंह (58) पिता राम सिंह 10 मई को गांव में छत पर पानी की टंकी भरने के दौरान गिर गए थे।

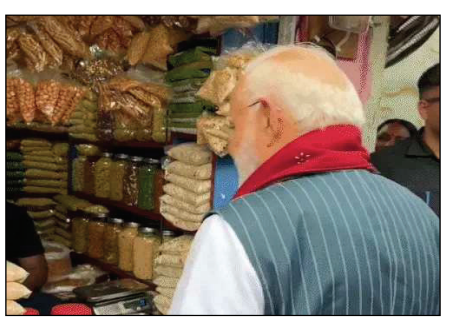

पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाकिस्तान-बांग्लादेश से धमकियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में झालमुड़ी बेचने वाले बिक्रम कुमार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बिक्रम की दुकान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खरीदकर खाई थी। इस घटना के बाद बिक्रम कुमार चर्चा में आ गए थे।

बिक्रम ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। बिक्रम ने बताया कि एक वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे। इसके चलते वे और उनका परिवार काफी तनाव में है।

राज्य सभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित

जयपुर(नि.सं.)। चुनाव आयोग ने राज्य सभा (Council of States) के द्विवार्षिक चुनाव (Biennial Elections) के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। 10 राज्यों से चुने गए राज्य सभा के 24 सदस्यों का कार्यकाल जून-जुलाई, 2026 में समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से चुने गए राज्य सभा के 3 सदस्य श्री नीरज डांगी, श्री राजेन्द्र गहलोत व श्री रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है।

आयोग ने सभी 24 सीटों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है:

अधिसूचना जारी होना: 01 जून, 2026 (सोमवार), नामांकन करने की अंतिम तिथि: 08 जून, 2026 (सोमवार), नामांकनों की जांच (Scrutiny): 09 जून, 2026 (मंगलवार)

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 11 जून, 2026 (गुरुवार), मतदान (Poll) की तिथि: 18 जून, 2026 (गुरुवार), मतदान का समय: सुबह 09.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक

मतगणना (Counting): 18 जून, 2026 (गुरुवार) शाम 05:00 बजे से, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तिथि: 20 जून, 2026 (शनिवार)

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर प्राथमिकता दर्ज करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान किए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग नहीं किया जा सकता। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों (observers) की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी।

रफ्तार का कहर | **जयपुर-सीकर हाईवे पर तेज रफ्तार में चाय की थड़ी को उड़ाया**

कार ने तीन युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत

खाटूश्यामजी जा रहे थे पति-पत्नी

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर-सीकर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने चाय की थड़ी को तोड़ते हुए युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। थड़ी पर मौजूद मालिक और एक कस्टमर घायल हो गए। घायल का कहना है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। एक्सीडेंट करने वाली टैक्सी कार से पति-पत्नी खाटूश्याम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने टैक्सी कार को जब्त कर ड्राइवर को राउंडअप किया है। SHO (दौलतपुरा) सुनील गोदारा ने बताया- हादसे में बलराम अटल (24) पुत्र बोदूराम अटल की मौत

हो गई। जो जयपुर ग्रामीण के अमरसर स्थित गांव मेहर खुर्द का रहने वाला था। घायल जोधपुर निवासी थानाराम और चाय थड़ी मालिक कैलाश सैनी निवासी मोटू का बास दौलतपुरा का प्राथमिक उपचार करवाया गया है।

दरअसल, जयपुर से एक पति-पत्नी ने खाटूश्यामजी दर्शन के लिए टैक्सी कार बुक की थी। शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे जयपुर-सीकर हाईवे पर मोटू का बास (जयपुर) से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हाईवे की सर्विस लाइन के साइड में मौजूद थड़ी में जा घुसी। चाय थड़ी पर मौजूद बलराम, थानाराम और कैलाश को कार ने चपेट में ले लिया।

कार के एयरबैग खुलने से बची जान

पुलिस के अनुसार, एक्सीडेंट होने पर कार के एयरबैग खुल गए। इससे कार ड्राइवर जितेंद्र सिंह और पीछे बैठे पति-पत्नी बच गए। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने दौलतपुरा पुलिस को सूचना देने के साथ ही ड्राइवर को पकड़कर मारपीट की।

मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बलराम को मृत घोषित कर शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी भिजवाया। घायल कैलाश और थानाराम को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रिक, प्रकाशन, संपादक - नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रिक एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झेलना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) प्रकाशित प्रबंध संपादक - पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)